

**मुख्यमंत्री ने जी०सी०सी० इनोवेशन समिट-2026 में
05 निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किए**

विभिन्न कम्पनियों व प्रदेश सरकार के मध्य 15 एम०ओ०यू० का आदान-प्रदान हुआ
प्रदेश के 13 प्रमुख विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों के साथ एम०ओ०यू० सम्पन्न

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, मेक इन इण्डिया,
सेमीकंडक्टर मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को गति मिली, देश
में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विकास के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध : मुख्यमंत्री

राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक प्रदेश में 04 करोड़
वर्ग फुट विश्वस्तरीय ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस के विकास में सहयोग
तथा 500 नए जी०सी०सी० स्थापित करने की दिशा में कार्य करना

जी०सी०सी० नीति-2024 के तहत कम्पनियों को भूमि सम्बन्धी
प्रोत्साहन, परिचालन व्यय सहायता, पेटेंट इंसेंटिव और
एस०जी०एस०टी० रीइम्बर्समेंट जैसी सुविधाओं का लाभ

उ०प्र० में आई०टी०, आई०टी०-सक्षम सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक
सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण से जुड़ी 230 से अधिक कम्पनियां कार्यरत

प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 02 लाख STEM स्नातक तैयार हो रहे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
पार्कों का विस्तार किया जा रहा, यीडा क्षेत्र में लगभग 25,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक
उपलब्ध, 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, थ्री-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स,
डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और
ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के
लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे

प्रदेश में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 35,000 करोड़ रु० के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

उ०प्र० की प्राचीन ज्ञान परम्परा को आधुनिक सन्दर्भ में जी०सी०सी०,
अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता

लखनऊ : 26 अक्टूबर, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेण्टर्स (जी०सी०सी०) के विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश को वैश्विक तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख केन्द्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक प्रदेश में 04 करोड़ वर्ग फुट विश्वस्तरीय ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस के विकास में सहयोग

करना तथा 500 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य करना है। तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स और साझा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में जी0सी0सी0 के विकास से प्रदेश में वैश्विक स्तर के कार्यों और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सकता है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां जी0सी0सी0 इनोवेशन समिट-2026 को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 05 निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किए। उनके समक्ष विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधियों व प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने आपस में 15 एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया। साथ ही, इस अवसर पर प्रदेश के 13 प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 सम्पन्न हुए। मुख्यमंत्री जी ने आई0आई0टी0 कानपुर और एच0सी0एल0 टेक द्वारा तैयार किए गए 'व्हाइट पेपर' का विमोचन किया। इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पर लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आधुनिक औद्योगिक विकास से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ज्ञान परम्परा से भी जुड़ी हुई है। माँ गंगा और यमुना जी की संगम स्थली प्रयागराज, प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि मथुरा तथा नैमिषारण्य जैसी ज्ञान परम्परा से जुड़ी स्थली उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती हैं।

भारतीय ज्ञान परम्परा ने सदैव विभिन्न स्रोतों से ज्ञान ग्रहण करने और विचारों के आदान-प्रदान को महत्व दिया है। 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए ज्ञान के सभी मार्ग खुले रहने चाहिए। प्रयागराज में कुम्भ और महाकुम्भ की परम्परा तथा काशी की ज्ञान परम्परा भारत में विचार-विमर्श, ज्ञान-विज्ञान और आदान-प्रदान के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसी परम्परा को आधुनिक सन्दर्भ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इण्डिया, स्मिल इण्डिया, मेक इन इण्डिया, सेमीकंडक्टर मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जैसे कार्यक्रमों को गति मिली है। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की है और देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विकास के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। प्रदेश में तकनीकी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक आधार तैयार किया गया है। उन्होंने उद्योग जगत से इन अवसरों का लाभ उठाने और प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जी०सी०सी० नीति-2024 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने वाली कम्पनियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। इनमें भूमि सम्बन्धी प्रोत्साहन, परिचालन व्यय सहायता, पेटेंट और एस०जी०एस०टी० रीइम्बर्समेंट जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने तथा प्रदेश के जी०सी०सी० ईकोसिस्टम को विकसित करने में सहभागी बनने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश में निवेश, नवाचार, तकनीक और रोजगार के नए अवसरों के विस्तार में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आई०टी०, आई०टी०-सक्षम सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण से जुड़ी 230 से अधिक कम्पनियां कार्यरत हैं। उन्होंने Microsoft, IBM, Adobe, NXP, TCS, HCL Technologies और L&T Semiconductor Technologies जैसी कम्पनियों का उल्लेख किया। उन्होंने LG Electronics, Haier, Dixon Technologies, Addverb और Vivo जैसी कम्पनियों की मौजूदगी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण का ईकोसिस्टम विकसित हुआ है।

आई०आई०टी० कानपुर के सहयोग से नोएडा में तथा आई०आई०आई०टी० लखनऊ और आई०आई०एम० लखनऊ के सहयोग से लखनऊ में डीपटेक हब स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, नई स्टार्टअप नीति और स्टेट ए०आई० मिशन के माध्यम से नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी०सी०सी० क्षेत्र के विकास के लिए कुशल, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 02 लाख STEM स्नातक तैयार हो रहे हैं। राज्य सरकार युवाओं को कौशल, नवाचार और तकनीक से जोड़कर उद्योगों के अनुरूप कार्यबल तैयार करने पर जोर दे रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, थ्री-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का विस्तार भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2017 से पहले लगभग 120 थी, जो बढ़कर 25,000 हो गई है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के बीच सहयोग से युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र आईटी0, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) क्षेत्र में लगभग 25,000 हेक्टेयर का लैण्ड बैंक उपलब्ध है। इस क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, एम0एस0एम0ई0 पार्क, डेटा सेंटर पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक्स हब जैसी परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना तथा उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से उन्नत विनिर्माण, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हुई हैं। उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परियोजना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई। इस परियोजना में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से कैम्पस चयन की व्यवस्था भी की गई। ब्रह्मोस परियोजना में लगभग 500 युवा इंजीनियर जुड़े हैं। प्रदेश में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 35,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं का प्रदेश है। प्रदेश की प्रगति और विकास की गति आज इन सम्भावनाओं को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में उद्योग, तकनीक, नवाचार, कुशल मानव संसाधन, आधारभूत संरचना और निवेश के अनुकूल नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी औद्योगिक पहचान और निवेश के वातावरण में व्यापक परिवर्तन किया है। वर्ष 2017 से पूर्व निवेशकों के सामने अनेक चुनौतियां थीं। निवेश के लिए आवश्यक सुरक्षा, आधारभूत संरचना और नीतिगत स्पष्टता को लेकर भी सवाल उठते थे।

वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों, भूमि बैंक, आधारभूत संरचना और औद्योगिक वातावरण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रदेश के पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 4.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास 36 सेक्टरल पॉलिसी हैं। प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड

ब्रेकिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं।

प्रदेश में उद्योगों और निवेशकों के लिए नीतिगत स्पष्टता, सुरक्षा और सुविधाजनक प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई है। राज्य सरकार निवेशकों से किए गए वादों और प्रोत्साहनों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम करने की दिशा में काम किया गया है। उत्तर प्रदेश ने विगत साढ़े नौ वर्षों में रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यु सरप्लस स्टेट है। राज्य का बजट देश के किसी भी राज्य के बजट की तुलना में सबसे बड़ा है। प्रदेश सरकार के बजट में 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च की जाती है। विगत वर्षों में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, बजट और महिला कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उद्योगों के विस्तार और निवेश के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। विगत साढ़े नौ वर्षों में राज्य में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विस्तार के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई सम्पर्क, सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक भूमि की उपलब्धता को मजबूत किया गया है। बिजली, सड़क, परिवहन और औद्योगिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता से प्रदेश में उद्योगों के संचालन और विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण बना है। देश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 75,000 एकड़ का भूमि बैंक उपलब्ध है। वर्ष 2017 में प्रदेश में 02 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, जबकि वर्तमान में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट और 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में इनलैण्ड वॉटर-वे की सुविधा तथा देश की पहली रीजनल रैपिड रेल सेवा की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 8,000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान संचालित हैं, जो उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण और कानून-व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं। विगत वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में हुए

बदलाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पर्वी और त्योहारों के दौरान शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश अब दंगामुक्त प्रदेश है। सुरक्षित वातावरण से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और युवाओं, व्यापारियों तथा उद्यमियों को अपने कार्यों का विस्तार करने का अवसर मिलता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण आधार हैं। एक जनपद—एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को पहचान और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में लगभग 96 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयां हैं, जिनमें 3 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। उन्होंने कोविड कालखण्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रदेश में बड़े कारखानों की संख्या वर्ष 2017 से पहले लगभग 14,000 थी, जो बढ़कर लगभग 35,000 हो गई है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत तथा इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत है। साइबर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर, एग्रीटेक, डीपटेक, मेडटेक, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और खेल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश, नवाचार और रोजगार की नई सम्भावनाएं विकसित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। विगत वर्ष प्रदेश में लगभग 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। उन्होंने काशी, अयोध्या और मथुरा—वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का उदाहरण देते हुए कहा कि पर्यटन से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, गाइड सेवा, स्थानीय दुकानदारों और अन्य व्यवसायों को आजीविका के अवसर मिलते हैं। पर्यटन और सेवा क्षेत्र का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करा सकता है।

कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नंदी' तथा विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स श्री आलोक कुमार, आई0आई0टी0 कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।